

ज्ञान तत्व (202)

- (क) शेर की सवारी और खतरें । इस लेख में इस्लाम, साम्यवाद तथा संघ परिवार द्वारा हिंसा की सहायता से प्राप्त विश्वस्तरीय उपलब्धियाँ तथा अब सिमी नक्सलवाद ,अभिनव भारत जैसे आतंकवादी संगठनों के खतरे के प्रभाव का उल्लेख हैं ।
- (ख) सोनियाँ मनमोहन जोड़ी के छः वर्ष –इसमें अच्छे नेता और वुरे नेताओं की पहचान बताकर हमारी प्राथमिकता पर चर्चा है ।
- (ग) प्रश्नोत्तर –महिला आरक्षण ।
- (घ) प्रश्नोत्तर–गांधी और विनोबा की तुलना और विवेचना ।
- (च) प्रश्नोत्तर–कृत्रिम उर्जा की मूल्य समीक्षा पर भरत झुनझुन वाला तथा सांसद एन के सिंह के विचारों की समीक्षा ।
- (छ) एम एस सिंगला का प्रेम विवाह पर विचार और उत्तर ।
- (ज) एम एस सिंगला का जनगण मन पर ।
- (झ) अपनों से अपनी बात में मेरी योजना ।

(क) शेर की सवारी का सुख और खतरा

शेर की सवारी में बहुत आनन्द भी है और लाभदायक भी होती है। शेर की सवारी से व्यक्ति की शारीरिक शक्ति कई गुना बढ़ जाया करती है। शत्रुओं का नाश करने में शेर स्वयं ही पर्याप्त होता है। यदि वह शेर आपकी शक्ति के साथ जुड़ जावे तो फिर उसकी शक्ति का कहना ही क्या । पौराणिक कथाओं में दुर्गा जी द्वारा स्थापित खूंखार राक्षसों का वध करने में मिली सफलता में शेर की भूमिका का पूरा पूरा योगदान रहा है। शेर के खतरनाक हिंसक स्वभाव को देखते हुए भी भारत की राज्य व्यवस्था शेर को सम्मान जनक स्थान पर स्थापित करती है यही इस बात का पर्याप्त प्रमाण है।

शेर की सवारी में जहाँ सुख है वहाँ खतरा भी बहुत है। शेर को जब शत्रु नहीं मिलते तो वह अपनी भूख मिटाने के लिये निर्दोष लोगों पर भी अक्रमण करना शुरू कर देता है। आप चाहकर भी शेर को इस अत्याचार से नहीं रोक सकते क्योंकि शेर के भोजन की व्यवस्था आपकी मजबूरी है। शेर बेगुनाहों पर अत्याचार करता है और आप चुप रहते हैं क्योंकि आपके पास कोई और उपाय नहीं है। किन्तु एक समय ऐसा भी आता है जब शेर को पेट भरने के लिये कोई और नहीं दिखता और तब वह शेर आपके लिये खतरा बन जाया करता है। आप शेर से मुक्त होने का बहुत प्रयत्न करते हैं किन्तु तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और तब आप उक्त शेर के लिये भोजन के रूप में काम आते हैं। श्रृष्टि का यही क्रम है जो पुराने समय से चल रहा है। अनेक लोग तो प्रारंभ से ही शेर की सवारी से दूरी बनाकर रखते हैं किन्तु कुछ ऐसे भी होते हैं जो इतिहास से सबक न सीखकर कुछ नया करना चाहते हैं और तब उन्हें पता चलता है कि शेर की सवारी में सुख तो बहुत मिलता है किन्तु खतरे भी कम नहीं होते ।

सामाजिक आधार पर हिन्दुत्व तथा राजनैतिक आधार पर लोकतंत्र ऐसी शेर की सवारी से बचना चाहता है। हिन्दुत्व में अहिंसा को बहुत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त रहा है। समाज तो हिंसा से अधिकतम दूरी बनाने की सलाह दी ही जाती है राज्य को संतुलित हिंसा की ही अनुमति होती। लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं होता। अपराधों को छोड़कर हिंसा सर्वत्र वर्जित रही है। वर्तमान विश्व में तीन ही प्रमुख समूह दिखते हैं जिन्होंने शेर की सवारी का आनन्द लिया (1) इस्लाम (2) साम्यवाद (3) संघ परिवार।

इस्लाम ने सबसे पहले हिंसा को सैद्धान्तिक आधार दिया। प्रारंभ से ही इस्लाम ने संगठन को शक्ति माना। गुण की अपेक्षा संख्या की चिन्ता का प्रारंभ इस्लाम से हुआ। न्याय की अपेक्षा अपनत्व के महत्व का विस्तार भी इस्लाम ने ही दिया। इस्लाम को इस शेर की सवारी का लाभ भी मिला। पिछले एक हजार वर्षों से इस्लाम लगातार आगे बढ़ रहा है। उसे सफलता ही सफलता मिलती रही। कुछ सूफी सन्तों ने इस्लाम का मार्ग बदलने की भी कोशिश की किन्तु वे किनारे पर दिये गये। बेचारे सूफी सन्तों की दरगाह पर चादर के अतिरिक्त उनके विचारों का कोई उपयोग नहीं। मुसलमानों के हिंसक स्वरूप की ढाल के रूप में ही सूफी विचारों का उपयोग किया जाता है।

भारत में इस्लाम की प्रगति का आधार शेर रूपी संगठन शक्ति की क्षमता ही है। पूरे भारत में इनका एक संगठित स्वरूप है जो विश्व इस्लामिक बिरादरी से संचालित है। इन्होंने धर्म और राजनीति का पूरा पूरा समन्वय भी कर रखा है। सभी राजनैतिक दल इनकी संगठन शक्ति के समक्ष समझौता करने को मजबूर है। भारत में योजना बद्ध तरीके से अपनी संख्या बढ़ाने का पूरा पूरा प्रयास करते रहते हैं। ये भारत में भी पूरे विश्व के समान ही सफलता की ओर बढ़ रहे हैं।

साम्यवाद ने भी संगठन शक्ति को आधार बनाया। इसने धर्म, समाज, गुण, आदि से स्वयं को दूर घोषित करके राज्य पर ही अधिकार करने की योजना बनाई। इसने भी हिंसा का पूरा पूरा समर्थन किया। बल्कि साम्यवाद ने तो इस्लाम से भी कुछ आगे जाकर हिंसा का पक्ष लिया। साम्यवाद ने संपूर्ण विश्व में जिस बेशर्मी से वर्ग संघर्ष का नारा दिया वैसी योजना तो इस्लाम भी नहीं दे सका। साम्यवाद ने विल्कुल खुलकर वर्ग संघर्ष की आवश्यकता स्थापित की। इसने कभी लोकतंत्र को स्वीकार नहीं किया। सर्वहारा वर्ग की तानाशाही को इसने आधार बनाया और पूंजीवाद को शत्रु। पूंजीवाद बनाम सर्वहारा का वर्ग निर्माण करके वर्ग संघर्ष का इसका नारा चल निकला और साम्यवाद का शेर दहाडता हुआ दुनियाँ की स्थापित व्यवस्था को रौंदता चला गया। अल्प काल में ही साम्यवाद लोकतंत्र के लिये खतरा दिखने लगा। यहाँ तक कि अनेक देश, जो सीधे सीधे साम्यवादी तानाशाही से सहमत नहीं थे, उन्होंने भी समाजवाद के नाम पर पूंजीवाद के विरुद्ध बीच का मार्ग निकाल लिया। साम्यवाद के विस्तार की गति इस्लाम से भी अधिक तेज थी। सफलता मिलती चली गई।

भारत में भी साम्यवाद तेजी से बढ़ा। नेहरू जी के नेतृत्व वाली भारत सरकार ने भी समाजवाद घोषित करके अपनी जान बचाई। नेहरू जी ने घोषित साम्यवाद और अघोषित साम्यवाद रूपी दो भाग बनाकर अघोषित साम्यवादियों को अपने साथ मिला लिया। इस तरह भारत में भी साम्यवाद दोनों दिशाओं से फलता फूलता रहा। तीन प्रदेशों में तो घोषित साम्यवाद और शेष भारत में समाजवाद के नाम से अघोषित साम्यवाद बढ़ता रहा। यदि लोहिया जी ने बाधा पैदा न की होती तो नेहरू जी तो उस राह पर चल ही रहे थे। साम्यवाद का विस्तार इतना तेज था कि अहिंसक गांधीवादी संस्थाएँ भी पूरी तरह साम्यवाद के प्रभाव में आ गईं। गांधी जी लोकतंत्र को लोक स्वराज्य की दिशा में ले जाना चाहते थे और साम्यवादी लोकस्वराज्य की अपेक्षा आर्थिक असमानता को आगे लाकर लोक स्वराज्य के मुद्दे को पीछे करना

चाहते थे । साम्यवादियों की सर्वोदय में इस सीमा तक घुस पैठ हुई कि सर्वोदय ने ग्राम स्वराज्य का अर्थ ही बदल दिया और स्वराज्य की जगह सुराज्य की माला जपने लगे ।

इस्लाम की शेर की सवारी की सफलता से प्रभावित होकर कुछ हिन्दुओं ने भी हिन्दुत्व की मूल अवधारणा “अहिंसक गाय की सवारी” छोड़कर शेर की सवारी का मार्ग चुना । इन्होंने भी संघे शक्ति कलौ युगे का नारा देना शुरू किया । इन्होंने समाज की जगह राष्ट्रवाद को आधार बनाया । राजनीति को इन्होंने अपने साथ जोड़ लिया । तर्क के स्थान पर भाई चारा का सहारा लिया गया । संघ परिवार ने भी हर उस मार्ग की दिशा में चलना शुरू किया जिस मार्ग से इस्लाम बढ़ रहा था । संघ परिवार इस्लाम और साम्यवाद की कार्य प्रणाली में सिर्फ एक ही फर्क था कि इस्लाम भारत में अल्पमत में होने के कारण छिपकर गुप्त योजनाओं पर काम करता था तो संघ परिवार बहुमत के घमंड में खुले आम दहाड़ते हुए ।

प्रारंभ से ही संघ परिवार की गति भी तेज रही । पूरे भारत में संघ परिवार भी बढ़ता चला गया । धन बल और कार्यकर्ताओं की इनके पास कभी कोई कमी नहीं रही । समाज शब्द को ही किनारे करके राष्ट्र शब्द स्थापित हुआ । हिन्दुत्व की वास्तविक शक्ति “विचार मंथन” का स्थान गाय गंगा ने ले लिया । संघ परिवार का विस्तार यहाँ तक हुआ कि वर्तमान में कई प्रदेशों में उसकी सरकारें सफलता पूर्वक चल रही हैं और आम चुनाव में वह सबसे बड़ी ताकत बनकर सामने आई ।

दुनियां में इस्लाम और साम्यवाद की शक्ति बढ़ी । भारत में भी इस्लाम, साम्यवाद, तथा संघ परिवार की शक्ति बढ़ती चली गई और वास्तविक हिन्दुत्व अल्प मत में आ गया । स्पष्ट दिखने लगा कि अब तर्क, अहिंसा, समाज व्यवस्था आदि बीते दिनों की बात है। अब तो संख्या बल की छीना झपटी ही हमारी एक मात्र सक्रियता है। संपूर्ण भारत में साम्यवादी, मुसलमान, इसाई और संघपरिवार के एजेन्ट घूम घूम कर हिन्दुओं का मत परिवर्तन करने लगे । यहाँ तक कि सरकार भी वर्ग संघर्ष को आधार बनाकर काम करने लगी ।

एकाएक स्थिति में बदलाव आया । तीनों ही संगठनों के कट्टरवादियों ने अपनी स्वतंत्र राह बनाई । साम्यवादियों पर नक्सलवादी, मुसलमानों पर सिमी जैसे संगठन तथा संघ परिवार पर अभिनव भारत जैसे आतंकवादी संगठन भारी पड़ने लगे । वैसे साम्यवाद स्वतः ही पूरी दुनियां से परास्त हो रहा है किन्तु नक्सलवाद ने उस रही सही कसर को भी पूरा कर दिया है। जो साम्यवादी नक्सलवाद को पुचकार कर रहे थे वही अब बंगाल में परेशान हैं। ये नक्सलवाद के विरुद्ध आवाज भी उठा रहे हैं। किन्तु इनकी आवाज मजाक के रूप में सुनी जा रही है। मुस्लिम जगत की तो हालत इनसे भी ज्यादा खराब है। आज दुनियां का हर मुसलमान संदेह की नजर से देखा जा रहा है। पड़ोस में बैठे मुसलमान की दाढ़ी या नाम ही पड़ोसी को सतर्क कर रहा है। भारत में धीरे धीरे ऐसा ही वातावरण बन रहा है। पहले मुसलमानों के विरोध प्रदर्शन को महत्व दिया जाता था किन्तु अब उसे आदत माना जाने लगा है। कुछ वैसा ही हाल संघ परिवार का भी शुरू हो चुका है। अभिनव भारत जैसी आतंकवादी घटनाएँ प्रकाश में आने के बाद संघ परिवार वालों को भी सफाई देते नहीं बन रहा ।

गांधी हत्या में संघ परिवार का कोई हाथ नहीं था। इसके बाद भी उस समय से आज तक गांधी हत्या का सर्वाधिक नुकसान संघ परिवार ही उठा रहा है। आज भी देश भर में हो रहे हिन्दू आतंकवादी आक्रमणों से संघ परिवार का कोई लेना देना नहीं है। किन्तु संघ परिवार का हर कार्यकर्ता इस मामले में बचाव पर है। उत्तर देते नहीं बन रहा है। संघ के एक वर्तमान प्रचारक देवेन्द्र गुप्ता जी की

गिरफ्तारी के बाद तो और भी जटिल स्थिति आ गई है। आपने लगातार हिंसा का समर्थन किया। किसी सिरफिरे ने हिंसा कर दी तो लपटों से आपके हाथ भी तो जलेंगे। यदि शेर की सवारी का आपने लाभ उठाया है तो शेर के खतरे कौन उठायेगा। साम्यवाद के तो अप्रासंगिक होने के कारण उससे कोई प्रश्न खड़े नहीं कर रहा। साथ ही साम्यवादी लगातार मुखर होकर नक्सलवाद के खिलाफ बढ़ चढ़ कर बोल रहे हैं। मुसलमानों का मामला भारत तक सीमित न होकर विश्व स्तरीय है। उनके लिये विश्व स्तरीय नीतियाँ बन रही हैं किन्तु संघ परिवार को हिन्दू बहुमत का कभी समर्थन नहीं मिल पाया है। अब जब ऐसी ऐसी घटनाएँ प्रकाश में आएँगी तब आपका क्या हाल होगा? अब तक संघ परिवार का उतना बुरा हाल नहीं हुआ है जितना साम्यवाद का हो रहा है अथवा मुसलमानों का दिख रहा है किन्तु यदि संघ परिवार ने अब भी हिंसा के समर्थन की राह नहीं छोड़ी तो उसका भी डूबना निश्चित समझिये।

मैं अंत में कहना चाहता हूँ कि शेर की सवारी का भरपूर लाभ इस्लाम ने भी उठाया है, साम्यवाद ने भी और संघ परिवार ने भी। अब सिमी नक्सलवाद तथा अभिनव भारत जैसे अतिवादी संगठनों के मैदान में आ जाने से आप तीनों के समक्ष संकट मुँह बाये खड़ा है। या तो तत्काल हिंसा के विरुद्ध घोषणा की पहल करिये अन्यथा परिणाम भुगतने को तैयार रहिये। शेर की सवारी का अब तक जैसा इतिहास रहा है, आप उससे बच नहीं सकते। रोकिये प्रवीण तोगडिया और अशोक सिंघल को। संकट का समय है। बचाव की मुद्रा हैं। उथल पुथल का वातावरण है। बहुत सोच विचार कर बयान देवे। किसी भी प्रकार की हिंसा का खुला विरोध शुरू कर दीजिये। कोई हिन्दू आपकी मदद के लिये नहीं आयेगा क्योंकि आम हिन्दू आंतकवाद से घृणा करता है। यह समय विस्तार की योजना का न होकर सुरक्षा की योजना का है। छोड़ दीजिये बड़ी बड़ी असंभव घोषणाएँ करना और थोड़ा झुककर धरातल देखियें। अहिंसा, विचार मंथन, तर्क, आदि हिन्दुत्व की मूल अवधारणाएँ स्थिति को संभाल सकती हैं। अन्यथा साम्यवाद, इस्लाम तथा संघ परिवार का भविष्य समाज एक साथ करेगा इसके आसार दिखने लगे हैं।

(ख) सोनियां मनमोहन जोड़ी के छः वर्ष

लगभग छः वर्ष पूर्व जब अटल जी के स्थान पर सोनिया जी के नेतृत्व पर जनता के विश्वास की मुहर लगी वह एक अजीब संयोग था अन्यथा उस समय का वातावरण तो पूरी तरह अटल जी के राजग के पक्ष में ही दिख रहा था। संप्रग सरकार बनते ही शंकाओं कुशंकाओं ने घर करना शुरू किया क्योंकि संप्रग को बहुमत दिलाने में वामपंथ की बहुत बड़ी भूमिका भी थी और सरकार को परेशान करने में वामपंथ की भूमिका का पुराना रेकार्ड भी साथ था। मनमोहन सोनिया जोड़ी ने सारी आशंकाओं को किनारे करते हुए सफलता पूर्वक वामपंथ दक्षिणपंथ की अवसरवादी एकता को धूल चटा दी और दुबारा फिर सरकार बना ली।

एक वर्ष पूर्व के चुनावों में जनता ने सभी राजनैतिक समीकरणों से दूर हटकर चरित्र को अधिक महत्व पूर्ण बनाया। केन्द्र में सोनिया मनमोहन सिंह पर विश्वास व्यक्त किया गया तो प्रदेशों में गुण दोष के आधार पर नरेन्द्र मोदी, रामण सिंह, नितिश कुमार, येदुरप्पा, गहलोत, नवीन पटनायक आदि व्यक्तिगत रूप से बढ़ाये गये। झारखंड में भी जनता ने अच्छी छवि वाले वावूलाल मराडी को कुछ मजबूत ही किया। एक आशा जगी कि राजनीति में भी शराफत मजबूत हो रही है।

छः वर्षों के कार्य की हम समीक्षा करें तो सामाजिक स्तर पर सोनिया मनमोहन जोड़ी ने कही सामाजिक चरित्र के उच्च मानदण्डों को कमजोर नहीं किया है। लालू, मुलायम, शिवु सोरेन, जयललीता, मायावती, ममता अर्जुन सिंह, अजित जोगी, प्रकाश करात जैसे तिकडम वाजों को लगातार कमजोर करने की मुहिम चलती रही और आज भी जारी है। यह तिकडमी समूह अब भी निराश तो नहीं हुआ है और उछल कूद लगातार जारी है किन्तु इन सबका व्यक्तिगत और सामूहिक अस्तित्व कुछ न कुछ घट ही रहा है। राष्ट्रीय मामलों में भी इस मनमोहन सोनिया जोड़ी ने कई अच्छे काम किये। नरेगा तथा सूचना का अधिकार तो ऐतिहासिक प्रयत्न माने ही जाते हैं, शिक्षा तथा खाद्य सुरक्षा विधेयक भी कुछ अच्छा ही करेंगे ऐसी संभावना है। अर्थनीति पूरी तरह सफल रही है। मंहगाई को मुद्दा बनाकर सरकार को अस्थिर करने का भाजपाई साम्यवादी अवसरवादी गठजोड़ भी ध्वस्त हो गया। सरकार धैर्य और शालीनता से सारे षडयंत्रों को असफल करती रही है। विदेश नीति भी पूरी तरह सफल ही मानी जा सकती है। सब प्रकार के अमेरिका विरोधी लावी व दबावों को किनारे करते हुए भारत ने अमेरिका आदि देशों से मित्रता को मजबूत कर लिया। बंगलादेश, श्रीलंका, नेपाल आदि के साथ भी कोई बचकानी हरकत नहीं हुई। चीन के मामले में भी गंभीर रूख ही रखा गया। पाकिस्तान के साथ भी सब कुछ समयानुकूल ही है।

साम्प्रदायिकता के मुद्दे पर सरकार ने राजनैतिक कारणों से थोड़ा सा मुस्लिम तुष्टीकरण की ओर झुकने की कोशिश की किन्तु शीघ्र ही संभल गये। कुल मिलाकर साम्प्रदायिक मामलों में भी सरकार की दिशा ठीक ही रही है। छः वर्षों के कार्यकाल में अन्य कोई भी ऐसा मामला देखने में नहीं आया जिसमें मनमोहन सोनिया जोड़ी ने राजनैतिक चरित्र पतन को प्रोत्साहित करने की कोशिश की हो।

पिछले छः महिनों से सोनिया जी कुछ गड़बड़ करती दिख रहीं हैं। अब तक सोनिया जी स्वयं को कांग्रेस की जगह देश का नेता समझकर राष्ट्रीय स्तर की चिन्ता कर रहीं थी किन्तु राहुल गांधी को प्रधान मंत्री बनाने की जल्दी में उनके स्तर में कमी आई है। मनमोहन सिंह चिदम्बरम् नक्सलवाद को राजनैतिक लाभ हानि से दूर रखकर राष्ट्रीय समस्या के रूप में सुलझाना चाहते हैं तो दूसरी ओर दिग्विजय सिंह आदि ने राहुल गांधी के माध्यम से इस इस समस्या को राजनैतिक लाभ हानि के तराजू पर तौलना शुरू कर दिया है। समझाया गया कि यदि केन्द्र सरकार को ही नक्सलवाद से निपटना हो तो क्यों नहीं कुछ दिन और बिगड़ने दें और जब इन प्रदेशों की कांग्रेस विरोधी सरकारों का पतन हो जावे तब केन्द्र हस्तक्षेप करके नक्सलवाद से निपट ले। आखिर एक ठीक चलती हुई लाइन को बिना कोई उपरी आश्वासन के दिग्विजय सिंह तो चुनौती दें नहीं सकते थे। अवश्य ही इसमें राहुल गांधी या सोनिया गांधी की संकीर्ण राजनैतिक इच्छाओं को जगाया गया होगा। हो सकता है कि सोनिया राहुल नक्सलवाद को अनियंत्रित चुनौती न मान रहे हो अथवा इनके मन में कोई और गंभीर योजना हो किन्तु अब तक के संकेत तो यही स्पष्ट करते हैं कि इनकी राजनैतिक तिकडमी भूख को जगाने में दिग्विजय सिंह सफल रहे हैं।

दूसरा मुद्दा है महिला आरक्षण का। सोनिया जी ने जिस तरह महिला और पुरुष के रूप में समाज को बांटने की मुहिम को हवा दी वह भी कोई अच्छी दिशा नहीं है। सोनिया जी को देश और समाज एक महिला नेता के रूप में नहीं देखता है। मैं मानता हूँ कि पश्चिमी संस्कारों के कारण उन्हें पारिवारिक संरचना के महत्व का ज्यादा ग्यान नहीं है किन्तु भारत में तो परिवार व्यवस्था का मजबूत होना एक अच्छी दिशा मानी जाती है। पारिवारिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने से सोनिया जी को दूर ही रहना चाहिये था। जो महिला और पुरुष स्वेच्छा से वैश्यालयों में इकट्ठे हो तब भी कानून और जो महिला और पुरुष नौकरियों में संसद में अन्य स्थानों पर दूरी बनाकर रखना चाहे तब भी कानून। महिला पुरुष के

प्राकृतिक, स्वाभाविक, पारिवारिक, सामाजिक रिश्तों में इस तरह अनावश्यक कानूनों की घुसपैठ क्यों? स्त्री और पुरुष के बीच पारिवारिक रिश्तों के बीच अविश्वास की खाई को चौड़ी करना और जब टूटने लगे तब तलाक के समय बाधा पैदा करना सरकारी ना समझी का प्रमाण है। गोवा के मुख्यमंत्री ने लाइन से हटकर महिलाओं के विषय में कुछ कह दिया तो अनुशासन भंग हो गया। मंत्रिमंडल के किसी सदस्य ने बाहर में कुछ कह दिया तब भी अनुशासन भंग हो गया किन्तु परिवार का कोई लडका लडकी परिवार में रहते हुये खुलेआम अनुशासन भंग करे उसे प्रोत्साहन। यदि किसी मंत्री को अनुशासन भंग से पूर्व मंत्रिपद छोड़ना नैतिकता है तो फिर लडका लडकी भी परिवार छोड़कर अनुशासन भंग करे तो कौन रोकता है? समाज व्यवस्था है कि महिला और पुरुष एक परिवार में शामिल होकर अपना स्वतंत्र अस्तित्व सीमित कर लेते हैं। या तो वे विवाह पूर्व के माता पिता के अनुशासन से बंधे हैं या विवाह के बाद पति पत्नी के आपसी अनुशासन से। इस परिवार व्यवस्था को कमजोर करके स्त्री पुरुष का वर्ग भेद मजबूत करना समाज के लिये हानिकारक है। हमें महिला और पुरुष सशक्तिकरण नहीं चाहिये और न ही भारतीय संस्कृति का कभी ऐसा आदर्श रहा है। हमें चाहिये परिवार सशक्तिकरण जिसमें महिला और पुरुष, युवक और वृद्ध एक साथ मिलकर सामंजस्य पूर्वक रह सकें। और यदि न रह सकें तो प्रेम पूर्वक अलग अलग हो जावें। किन्तु जब तक एक साथ है तब तक उसी तरह अनुशासन को समझें जैसे मंत्रिमंडल में या किसी राजनैतिक दल में अनुशासन मानते हैं। व्यक्ति परिवार और समाज के अधिकारों की सीमाएँ तय होनी चाहिये किन्तु इन सीमाओं के अन्दर तोड़ फोड़ का कोई बाहरी षड्यंत्र कभी नहीं होना चाहिये। जाने अनजाने सोनिया जी से वैसी भूल हो रही है।

आज पूरे भारत के राजनैतिक वातावरण में महिला आरक्षण के पक्ष में हवा है। सोनिया जी उसका लाभ उठाना चाहती है। मैं नहीं चाहता कि सोनिया जी आरक्षण का विरोध करके उस लाभ को ठोकर मारें। मैं चाहता हूँ कि सोनिया जी आरक्षण मुद्दे को व्यक्तिगत मुद्दा बनाने की भूल न करें। इतिहास आपको परिवार व्यवस्था को पलीता लगाने वाली महिला के रूप में याद करने लगेगा। तात्कालिक लाभ के उद्देश्य से दीर्घकालिक सामाजिक क्षति से आप स्वयं को पिछले छः वर्षों से दूर रखती रहीं हैं और उनका लाभ भी आपको समाज ने भरपूर दिया है तो अब धैर्य तोड़ना ठीक नहीं। जिस तरह छः वर्षों से अपनी गरिमा बनाकर रखी है वह गरिमा अब राजनैतिक लाभ हानि की कसौटी से धूमिल करना ठीक नहीं। दिग्विजय सिंह के नक्सलवादियों के साथ कैसे रिश्ते हैं, संपूर्ण देश जाने या न जाने किन्तु छत्तीसगढ़ का बच्चा बच्चा जानता है। आप उनकी सलाह पर राष्ट्रीय सुरक्षा के मापदंड बना रहीं हैं। इसी तरह साम्यवादियों की परिवार व्यवस्था के संबंध में धारणा भी जग जाहिर है। भारतीय जनता पार्टी का केन्द्रीय नेतृत्व सत्ता लोलुपों के जमघट से अधिक कुछ बचा ही नहीं। ऐसे दलों के उकसाने पर आपका महिला स्वाभिमान जग गया है। ये दोनों ही बातें अच्छे संकेत नहीं हैं। अभी तो अन्तिम निर्णय होना बाकी है। और आप सोच समझकर निर्णय करेंगी ऐसी उम्मीद है किन्तु सतर्क करना मेरा कर्तव्य था जो मैंने किया।

छः वर्षों के राजनैतिक लेखे जोखे में कुल मिलाकर मनमोहन सिंह सौ प्रतिशत और सोनिया गांधी निन्यानवे प्रतिशत खरे उतरे हैं। अब तक कोई दाग नहीं लगा है। विपक्षी दलों की सरकारों से भी इन्होंने शालीन ही व्यवहार किया है। दूसरी ओर विपक्षी भाजपा का आकलन करे तो इनके केन्द्रीय नेतृत्व को सौ में से एक अंक देने में भी दिक्कत हो रही है। इनका केन्द्रीय नेतृत्व इस सीमा तक तिकड़मी हो गया कि वह वामपंथियों तक से हाथ मिलाने को तैयार हो गया। इन्होंने मुस्लिम आतंकवाद की आवश्यकता से ज्यादा निंदा की और हिन्दू आतंकवाद को स्वाभाविक से ज्यादा समर्थन दिया। कांग्रेस के थूके हुए को

चाटने में इन्होंने बहुत अधिक जल्दबाजी की । शिवू सोरेन की ताजपोशी ने तो अत्यन्त ही हास्यास्पद स्थिति बना दी । इन्होंने अटल जी के कार्यकाल में कई बार डीजल पेट्रोल के मूल्य बढ़ाये किन्तु मनमोहन सिंह द्वारा डीजल पेट्रोल मूल्य वृद्धि के विरुद्ध वामपंथियों की गोद में जा बैठे । अवसरवादिता का कीर्तिमान स्थापित किया गया । ऐसी स्थिति में मैं इनके केन्द्रीय नेतृत्व को शून्य से अधिक क्या अंक दूँ । इनकी प्रादेशिक सरकारों ने अवश्य ही इनकी लाज बचा रखी है अन्यथा इनका केन्द्रीय नेतृत्व तो डूबा हुआ ही मानना चाहिये । यदि ये दस पांच पैसा भी रमण सिंह जी से सलाह लिये होते तो ऐसी दुर्गति कभी नहीं होती ।

कुल मिलाकर मैं यह कह सकता हूँ कि भारतीय राजनीति की वर्तमान स्थिति में आशा की किरणें कुछ मजबूत हुई हैं । सोनिया, मनमोहन, चिदम्बरम् की लाइन लगभग संतोष प्रद है । अडवानी जी करात जी आदि यदि किसी प्रादेशिक चरित्र को आगे आने दे तो देश का और भी अधिक सौभाग्य होगा । जो कुछ होगा अच्छा ही होगा । ऐसी उम्मीद दिख रही है । भविष्य निराशा जनक नहीं मानना चाहिये ।

(ग) कार्यालयीन प्रश्नों के उत्तर

(1) प्रश्न — इस लेख में आपने महिला आरक्षण का विरोध किया । महिलाओं पर अत्याचार आप किस प्रकार रोकेंगे?

उत्तर— महिला पुरुष युवक वृद्ध व्यक्तिगत रूप से पृथक हैं किन्तु सामूहिक रूप से पृथक पृथक मानना घातक परंपरा है । ये सब मिलकर परिवार बनते हैं । परिवार बनते ही इनकी पृथक पहचान समाप्त हो जाती है और रह जाती है एक पारिवारिक पहचान । इनमें से किसी एक का भी सृजन स्वतंत्र नहीं होता । कोई यह नहीं कह सकता कि वह नारी से उत्पन्न है या नर से । नर और नारी के एकाकार प्रयास से संतान उत्पन्न होती है और एकाकार प्रयास से ही पूरा जीवन समाप्त करते हैं । समाज ने इन्हे व्यक्तिगत रूप से कुछ मौलिक अधिकारों की सुरक्षा का वचन दिया है । इसके आगे वे परिवार के अंग मात्र हैं ।

जब पुरुष और महिला पृथक पृथक वर्ग है ही नहीं तो वर्ग के रूप में चिन्तन की आवश्यकता ही नहीं है । हजारों वर्षों से पृथक पृथक वर्ग की मान्यता ने ही समस्याएँ पैदा की हैं । प्राचीन समय में स्वार्थी पुरुषों ने महिलाओं को पृथक वर्ग कहकर उनपर तरह तरह के आरोप जड़ दिये । अब स्वार्थी महिलाएँ पुरुषों को वर्ग घोषित करके अत्याचार के आरोप जड़ रही हैं । मैं जब भी किसी सभा में जाता हूँ तो यदि उस सभा में एक भी महिला राजनीति से जुड़ी होगी तो वर्ग विद्वेष की चर्चा अवश्य करेगी । यह घातक है । आज समाज में निन्यानवे प्रतिशत लोग स्त्री और पुरुष को पृथक पृथक वर्ग के रूप में मानने लगे हैं जो पुरी तरह असत्य है ।

किसी महिला के साथ अत्याचार हो सकता है । उसके लिये कानून है । किन्तु महिलाएँ और पुरुष बहुवचन होते ही नहीं क्योंकि न उनका जन्म स्वतंत्र हुआ है न ही स्वतंत्र जन्म दे सकते हैं । किसी प्रकार के अलग कानून बन ही नहीं सकते क्योंकि उनका पृथक अस्तित्व ही नहीं है । महिला पुरुष के बीच अत्याचार की जो अतिरंजित कहानियाँ बताई जाती हैं, उनमें अनेक तो प्राकृतिक आवश्यकता हैं । स्त्री और पुरुष विवाह उपरान्त पति पत्नी बन जाते हैं । दोनों के सुखी जीवन के लिये पति की आक्रामक ।जजंबापदह मुद्रा तथा स्त्री की आकर्षक ।जजतंबजपदह मुद्रा होनी चाहिये । यदि यह मुद्रा उलट जावे तो

परिवार का इलाज कराना पड़ेगा। इस अन्तर की सीमा तय हो सकती है। यदि अंतर उस सीमा से अधिक हो और आपस में पारिवारिक समझौते या सामाजिक अनुशासन से ठीक न हो तब कानून का हस्तक्षेप हो। यहाँ तो कोई सीमा ही तय नहीं है। न्यायाधीश पति पत्नी के आंतरिक सम्बन्धों पर निर्णय देते हैं कि पत्नी की सहमति के बिना किया गया सम्भोग बलात्कार माना जायगा। आचार्य पंकज जी ने एक किताब लिखी है "सम्यक संभोग, सदा निरोग"। पुस्तक के अनुसार पुरुष को हमेशा आक्रामक होना चाहिये। जज के अनुसार पत्नी की सहमति होनी चाहिये। क्या सीमा रेखा हो यह न पति पत्नी तय करेंगे न परिवार न समाज। तय करेगा कानून या कोर्ट। सेक्स के लिये भूखे दो स्त्री और पुरुष को दरोगा रोकेगा। बेशर्मी तो इस सीमा तक है कि सरकार वैश्यालयों पर भी टैक्स लगाना चाहती है। भारत में अपना शरीर बेचकर भरण पोषण को मजबूर महिलाओं की मजबूर आमदनी पर भी सरकार टैक्स लगायेगी। जबकि उसे शर्म करना चाहिये कि कोई पेट भरने को मजबूर महिला वैश्यावृत्ति कर रही है।

मेरा आशय सिर्फ यही है कि महिला उत्पीड़न को स्वीकार करना बहुत घातक परंपरा है क्योंकि महिला उत्पीड़न को स्वीकार करने का मतलब है दोनों को पृथक वर्ग स्वीकार करना। यह स्वीकार बहुत हानिकारक है।

(घ)(2) प्रश्न – आपके नाम से निर्दलीय साप्ताहिक में प्रकाशित गांधी और विनोबा के संबंध में एक विवेचना पढ़ी जो इस प्रकार है। "वर्षों की स्वतंत्रता के बाद भी हम भारत में भय या भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था देने में सफल नहीं हो रहे हैं क्योंकि हमने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज्य की परिभाषा को छोड़ अपनी नयी परिभाषा बना ली। गांधी जी गांवों को अपने निर्माण की स्वतंत्रता हमारा दायित्व मानते थे और अन्य कार्यों को हमारी सलाह। हमने गांवों को अपने निर्णय की स्वतंत्रता दिये बिना ही विकास की योजनाएँ बनानी शुरू कर दी जिनका दुष्परिणाम हुआ भ्रष्टाचार, अन्याय व आतंकवाद आदि। स्वशासन का परिणाम है सुशासन न कि स्वशासन सुशासन का आधार है किन्तु हमने पहले सुशासन के प्रयास शुरू किये जो बिल्कुल असंभव कार्य था।

गांधी की हत्या के तत्काल बाद गांधी जनो का नेतृत्व विनोबा जी को दिया गया। गांधी जी व विनोबा में बहुत फर्क था। गांधी जी एक मौलिक विचारक थे। और विनोबा जी उच्च कोटि के विद्वान। गांधी जी सामाजिक राजनीति के ज्ञाता थे और विनोबा जी धार्मिक सामाजिक विषयों के। विनोबा जी को राजनीतिक छल प्रपंच का ज्ञान नगण्य था। गांधी जी समझदारी प्रधान थे तो विनोबा जी शराफत प्रधान। गांधी महापुरुष थे और विनोबा जी संत पुरुष। गांधी जी का त्याग वैचारिक था और विनोबा जी का भावनात्मक। गांधी जी परिपाटी बनाने की क्षमता रखते थे और विनोबा जी बनी बनाई परंपरा पर चल सकते थे। गांधी जी सूर्य थे और विनोबा जी चन्द्रमा। गांधी में सूर्य के समान उष्णता थी और विनोबाजी में चन्द्रमा के समान शीतलता।

यही कारण था कि गांधी जी ने सदा संघर्ष को प्राथमिकता दी और विनोबा जी ने संघर्ष को टंडा करने में। गांधी जी यदि जीवित होते तो पद लोलुप नेताओं से टकराव होता। दूसरी ओर गांधी जी के ही पद चिन्हों पर चलने का दावा करने वाले विनोबा जी राजनेताओं को खुली छूट दे स्वयं भूदान आंदोलन में लग गये। भूदान आंदोलन एक सामाजिक समस्या के समाधान का कार्य तो था किन्तु लोक स्वराज्य संघर्ष का कार्य नहीं था। मगर विनोबा जी ने किया। उन्होंने कांचन मुक्ति व राजनीति से दूरी बनाने की बात कहकर सर्वोदय कार्यकर्ताओं को विषविहीन सर्प बना दिया जो या तो संघर्ष से दूर हो गये और समाज सेवा में लग गये अथवा राजनेताओं के पिछलग्गू बन गये। विनोबा जी ने वर्ष 1942 में

स्वराज्य शास्त्र पुस्तक रची । लोकनायक जय प्रकाश नारायण ने वर्ष 1954 में लोक स्वराज्य पर बहुत अच्छी पुस्तक रची । डॉ० राममनोहर लोहिया चौखम्बा राज्य की वकालत करते रहे । किन्तु गांधी हत्या के बाद योजना पूर्वक गांधी की स्वराज्य की अवधारणा को लगातार चर्चा से दूर किया गया। पंडित जवाहर लाल नेहरू डॉ० बाबा साहब अम्बेडकर व सरदार वल्लभ भाई पटेल आदि इतने हावी हुए कि पूरे भारत में सुशासन की मांग बढ़ती गई और स्वशासन की भूख घटती गई । यह भूख इस सीमा तक घटी कि भारत की अधिकांश आबादी राज्य की मुख्यापेक्षी हो गई ।

लिहाजा हम राज्य से स्वशासन की मांग न कर समाधान की मांग करने लगे हैं । यहाँ तक कि सर्वोदय कार्यकर्ता भी इससे अलग नहीं हैं । हमें चाहिये कि हम शासन के अधिकारों का विरोध करें किन्तु हम शासन के अधिकारों का विरोध न कर आदेशों का विरोध करने लगते हैं । परिणाम यह है कि शासन के अधिकार बढ़ते चले गये हैं और हम अनावश्यक संघर्ष करते चले आ रहे हैं ।

हमारे वयोवृद्ध विचारक स्वतंत्रता सेनानी व वर्धा (महाराष्ट्र) वासी संघर्ष के प्रतीक ठाकुर दास बंग ने कई बार राज्य के अधिकारों के विरुद्ध संघर्ष की आवाज उठाई किन्तु वह आवाज सर्वोदय के सत्ता धड़ों को पसंद नहीं आई और किसी न किसी तरह उन्हें रोक दिया गया । अंत में लाचार होकर उन्होंने 20 सितम्बर 2008 को सेवा ग्राम आश्रम (वर्धा) की बैठक में लोक स्वराज्य अभियान शुरू करने की घोषणा की जो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है ।

स्वाभाविक है कि कुछ लोगों को यह अभियान पसंद न आया क्योंकि यह अभियान मुख्यरूप से संविधान में परिवार , गांव व जिले के अधिकारों की सूची शामिल करने तथा निर्वाचित जन प्रतिनिधि को वापस बुलाने के अधिकार की मांग को लेकर है । यह आंदोलन सर्वोदय परिवार के अन्य क्रियाकलापों में कहीं बाधक नहीं है किन्तु फिर भी कुछ लोग किसी न किसी बहाने इस अभियान के विरुद्ध भ्रम फैलाते रहते हैं । यह अभियान तत्काल सरकारी वेतन से जुड़े लोगों की मनमानी वेतन वृद्धि के विरुद्ध भी जागृति का कार्यक्रम चलाया है । तथा लगातार इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं । लोक स्वराज्य अभियान सर्वोदय के अन्य कार्य के अतिरिक्त यह कार्य भी कर रहा है जिसमें सर्वोदय से अलग लोग भी जुड़ते जा रहे हैं ।

मुझे महसूस होता है कि बंग जी के नेतृत्व में प्रारंभ लोक स्वराज्य अभियान की सफलता आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है । यह अभियान गांधी विनोबा जय प्रकाश के अधूरे कार्य को आगे बढ़ाने का श्रेष्ठतम मार्ग है । नफरत की आग में जलने वालों से प्रभावित हुए बिना इस अभियान को समझने की आवश्यकता है । मेरा आपसे निवेदन है कि आप लोक स्वराज्य अभियान से जुड़े और गांधी जी की अंतिम योजना को साकार करें ।”

इस विवेचना में विनोबा जी के विषय में कुछ निम्न कोटि के आरोप लगाये गये हैं । जो उचित नहीं हैं । हो सकता है कि गांधी जी की क्षमता विनोबा जी से ज्यादा भी हो किन्तु गांधी जी के बाद तो विनोबा के समकक्ष भी कोई नहीं था । विनोबा जी ने अपने जीवन काल में जो कुछ किया उस सीमा को भी तो बाद में कोई नहीं छू सका । हम चाहते हैं कि आप विनोबा जी के विरुद्ध लिखना बन्द कर सकें तो बहुत अच्छा होगा । हम विनोबा जी की झूठी आलोचना नहीं सुन सकते ।

उत्तर— मैंने गांधी और विनोबा की समीक्षा करते समय सब प्रकार की मर्यादाओं का ध्यान रखा था क्योंकि मेरा उद्देश्य विनोबा जी की आलोचना करना नहीं था। किन्तु विनोबा जी की समीक्षा करना तो था आप समीक्षा से हटकर विनोबा जी के प्रशंसक हैं तो मुझे भी विनोबा जी की आलोचना करने का उतना ही अधिकार है जितना आपको प्रशंसा करने का। विनोबा जी की नेहरू परिवार के प्रति गुप्त वचन बद्धता या आसक्ति ने भारत में गांधी विचार को बहुत पीछे ढकेल कर रख दिया। विनोबा जी ने लोक स्वराज्य की अवधारणा को नेहरू आसक्ति के कारण ही पीछे ढकेल दिया अन्यथा कोई कारण नहीं था कि गांधी के जाते ही गांधीवादी इस तरह गुमराह हो जाते। गांधीवादियों को उस समय ग्राम स्वराज्य के लिये नेहरू सरकार से संघर्ष करना था किन्तु विनोबा के कारण गांधीवादी नेहरू सरकार से संघर्ष का मार्ग छोड़कर भूदान में लग गये। परिणाम स्वरूप राजनेता स्वतंत्र से आगे बढ़कर उच्छ्रृंखल होते गये। यदि विनोबा जी जय प्रकाश जी को नैतिक समर्थन देते तो जे. पी. इस सीमा तक राजनेताओं पर निर्भर नहीं होते। जे. पी. असफल नहीं होते यदि संयुक्त सर्वोदय के हाथ में कमान रही होती।

विनोबा जी किस सीमा तक नेहरू परिवार के मोहजाल से लिप्त थे इसका उदाहरण हमारे इतिहास के जानकार ईश्वर दयाल जी ने बताया कि विनोबा ने इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री काल में कभी गोहत्या बंदी को जीवन मरण का प्रश्न नहीं बनाया। किन्तु इंदिरा जी के हटते ही विनोबा जी ने मुरारजी देसाई काल में गोहत्या बंदी को अपने जीवन के साथ जोड़कर आमरण अनशन कर दिया। मुरार जी भाई ने इस शर्त पर गोहत्या बंदी स्वीकार कर ली कि राज्य सभा में कांग्रेस भी समर्थन करे क्योंकि राज्य सभा में सरकार अल्पमत में थी। लोकसभा में विल पास हो गया किन्तु राज्य सभा में कांग्रेस ने इन्कार कर दिया। शीघ्र ही मुरार जी सरकार हट गई और इंदिरा जी प्रधानमंत्री बनीं तो विनोबा जी अनशन करना भूल गये। विनोबा जी के गुप्त नेहरू परिवार मोह के कारण ही आज सर्वोदय के अनेक उच्च लोग लोक स्वराज्य आंदोलन को पलीता लगाते रहते हैं।

मैं नहीं चाहता कि गड़े मुर्दे मैदान में आवे। विनोबा जी की चर्चा का अब कोई उपयोग नहीं किन्तु विनोबा जी के बताये मार्ग की समीक्षा तो करनी ही चाहिये। मेरा मत है कि हम गांधी और विनोबा की ठीक से समीक्षा करें और विनोबा की राजनेता अंध भक्ति की सलाह से हटकर राजनीति की गलत नीतियों के विरुद्ध गांधीवादी संघर्ष की राह पर चलना शुरू करें।

(च) प्रश्नोत्तर

(2) श्री एन के सिंह, राज्य सभा सदस्य, अर्थ शास्त्री, जदयू, विहार

सुझाव – भारत में बिजली का अभाव संकट के रूप में खड़ा हो गया है। इसमें पॉच मुद्दे विचारणीय हैं।

- (1) भारत में बिजली की उपलब्धता प्रतिव्यक्ति सात सौ कि. वाट है जबकि अमेरिका में चौरासी सौ है। हमारी खपत तो चीन से भी आधी है।
- (2) भारत में बिजली बहुत मंहगी है।
- (3) उपलब्धता अनिश्चित है।
- (4) उत्पादन और मांग के बीच भारी अंतर है।
- (5) कर्मचारियों का वेतन बढ़े अन्यथा अच्छे कर्मचारियों का अभाव हो जायगा।

(3) श्री भरत झुनझुनवाला ,प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ,

- (1) भारत में प्रत्येक व्यक्ति की आय और बिजली की खपत दोनों की साथ साथ तुलना करनी चाहिये।
- (2) भारत में बिजली उत्पादन से पर्यावरण को भारी क्षति होती है। क्योंकि भारी मात्रा में कोयला या डीजल खर्च होता है। बिजली पर सात रूपया प्रति युनिट का पर्यावरण टैक्स लगा कर उसे मंहगा कर देना चाहिये।
- (3) बिजली की मूल्य वृद्धि के बाद उसका उत्पादन लाभकारी हो जायगा। उत्पादन वृद्धि स्वयंमेव होगी। सौर उर्जा या गोबर गैस उत्पादन बढ़ेगा। खपत घटेगी सब इस प्रकार के लाभ होंगे।
- (4) बिजली की मूल्य वृद्धि से भारत सरकार को प्रति माह चार सौ अरब रूपया प्राप्त होगा। यह राशि गरीब परिवारों को बराबर बराबर बांट सकते हैं। सरकार की लोकप्रियता भी बढ़ेगी। तथा समस्या का भी समाधान हो जायगा। वेतन विसंगति भी दूर कर सकते हैं। यदि हमारे देश का उत्पादन मंहगा होने से आयात निर्यात प्रभावित हो तो प्राप्त पर्यावरण कर का एक भाग उसकी दर सुधारने पर भी लगा सकते हैं।

उत्तर – भरत झुनझुनवाला जी अर्थ शास्त्र के साथ साथ समाज शास्त्र के तालमेल की चिन्ता करते हैं और एन के सिंह जी अर्थशास्त्र का राजनीति शास्त्र के साथ का तालमेल बनाते हैं। यही कारण है कि एन के सिंह जी सस्ती बिजली के पक्षधर हैं और झुनझुनवाला जी मंहगी बिजली के। एन के सिंह जी जदयू की ओर से राज्य सभा सदस्य हैं। अपने दल की नीतियों के पक्ष में बोलना उनकी मजबूरी है। अभी करीब तीन माह पूर्व ही स्वतंत्र चर्चा में उन्होंने कहा था कि तटस्थ विचारक के रूप में कृत्रिम उर्जा की मूल्य वृद्धि उचित कदम है किन्तु राजनैतिक दृष्टि से यह कदम सरकार के लिये बहुत अधिक अलोकप्रिय होगा।

श्री एन के सिंह जी ए. पी.डी. आर. पी. के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। ए. पी.डी. आर. पी. बिजली के संबंध में विचार मंथन करके नीति निर्माण करती है। यह सरकारी सस्था है। एन के सिंह जी को बिजली के विषय में सोचना था जो उन्होंने सोंच सोंच कर सलाह दी। मेरे खेत में एक बूढ़ा यादव भैस चराता था। उसे भैस के हितों की तो चिन्ता रहती थी किन्तु खेत की फसल की चिन्ता नहीं रहती थी। यदि कभी मौका मिला तो मेरी हरी खेती चराने में भी उसे कष्ट नहीं होता था क्योंकि उसका मोह फसल की अपेक्षा भैस के स्वास्थ्य के प्रति अधिक जुड़ा था। यदि वह बूढ़ा यादव भैस विभाग से हटकर खेत सुरक्षा का प्रबंधक होता तो उसकी भूमिका भिन्न होती। एन के सिंह जी ने जो भी तर्क दिये उनमें उनकी वफादारी तो झलकती है किन्तु यथार्थ नहीं। एन के सिंह जी ने बिजली और श्रम के संबंधों पर कभी नहीं सोचा कि सस्ती उर्जा श्रम की मांग और मूल्य पर क्या प्रभाव डाल सकती है। यदि श्री सिंह श्रम विभाग से संबधित होते तो यही एन के सिंह जी बिजली का मूल्य तीन गुना करने की सिफारिश करते क्योंकि उस स्थिति में उनका पूरा सोच ही बदल जाता। झुनझुनवाला जी भी स्वतंत्र हैं और मैं तो हूँ ही। हमें बिजली के मूल्य की चिन्ता न होकर उससे गरीब ग्रामीण श्रमजीवी पर पडने वाले प्रभाव की चिन्ता है। श्री सिंह ने सम्पन्न देशों के आकडे देकर कुछ बातें कही हैं। उन्हें यह नहीं पता कि उन सम्पन्न देशों की प्राथमिक समस्या गरीब ग्रामीण श्रम जीवी नहीं है। एक भूखे श्रमिक को बीस रूपया मिले और वह मक्का की रोटी न खाकर किशमिश खाने की चिन्ता करे तो भूल किसकी है? यहां तो एन के सिंह जी सौ रूपया दैनिक में काम न पा सकने वाले बेरोजगार को सस्ती बिजली, सस्ता डीजल, सस्ती शिक्षा, आदि सबकी सलाह तो दे रहे हैं। किन्तु श्रम की मांग और मूल्य वृद्धि के विषय में चुप हैं क्योंकि यह विषय उनका नहीं है। श्रम और उर्जा के संबंधों की स्वतंत्रता पूर्वक समीक्षा करनी होगी। ये दलों की सीमाओं से

बधे लोगो के वक्तव्य गुमराह कर सकते है क्योकि वे स्वतंत्र भी नही है, और उनका स्वतंत्र ज्ञान भी नही है।

(छ) (4) श्री एम एस सिंगला , अजमेर, राजस्थान

प्रश्न – ज्ञान तत्व 182 जातीय पंचायत और प्रेम विवाह पर विस्तृत चर्चा पढने को मिली । इस विषय पर एक स्थानीय दैनिक के 'परिवार' पत्रिका मे भी सामग्री देखी थी । स्वाभाविक है कि दैनिक की सामग्री मे पत्रकारिता के अनुरूप कुछ भडकाउपन मिला जैसे आदिम सोच, वर्तमान प्रगतिशील युग की दुहाई आदि । यहाँ विषय से जुड़े कुछ चुने गये बिन्दुओ पर चर्चा करके समस्या के मूल मे जाने का प्रयास प्रस्तुत हैं ।

1 विवाह – मूल रूप से विवाह हृदय से संबन्धित मामला है। इसलिये पुरातन व्यवस्था के अनुसार अपनी पसंद की युवती को भगा ले जाना विवाह होता था । कालान्तर मे देशकाल के अनुसार व्यवस्था मे परिवर्तन होते आये । जिस व्यवस्था का उपर उल्लेख किया गया है उसके उदाहरण आदिवासी क्षेत्रो मे आज भी देखने को मिलते है जिन्हे समाज मे मान्यता प्राप्त होती है।

2. ज्ञान का अभाव– भारत मे प्रचलित दहेज ,सती, पर्दा, जैसी अन्याय प्रथाये और मान्यताएँ है । उनके विरोध मे उनके इतिहास ,उनके मूल्य ,उनके कारण , उनके वास्तविक स्वरूप आदि को जाने विना उन पर चोट करना शुरु कर दिया जाता है ।आजादी के बाद से तो राजनीति मे भी अपनी पैठ बनानी शुरु कर दी है। जो वस्तुतः अनावश्यक है। जनता मे भी एक टेव पडी दिखाई देती है कि वह छोटी छोटी बातो को लेकर सरकार का मुँह ताकती है और सरकार यह दिशा निर्देश देने की बजाय कि इसे तो समाज को ही संभाल लेना चाहिये , वह भूल जाती है कि जनता हर बात के लिये सरकार का मुह देखने लगी है ।

3 सामाजिक व्यवस्था और कानून– इन दोनो के अपने अपने क्षेत्र है। उन्हे वैसे ही अपने अपने दायरे मे रहने देना उचित है। परन्तु प्रायः दिन प्रति दिन हर स्थिति में विधि शरणं गच्छामी की स्थिति बन जाती है। मूलतः कानून अपराध पर नियंत्रण करने के लिये होता है । अपराध प्रायः वह घटना या प्रक्रिया या कृत्य होता है जो छिप कर किसी को आर्थिक –शारीरिक नुकसान पहुचाने के लिये किया जाता है । किसी को अंधेरे मे रखकर किया गया कृत्य भी अपराध है जिससे आगे चलकर उस व्यक्ति को किसी प्रकार की हानि उठानी पडे। परन्तु जो तथा कथित गलत काम सार्वजनिक रूप से खुले आम समाज द्वारा किया जाता है वह अपराध की श्रेणी मे न आकर कुप्रथा की श्रेणी मे आता है। यहां तथा कथित शब्द का प्रयोग इसलिये हुआ है कि यदि वह कृत्य अपराध ही हो तो समाज उसे करेगा ही नही । अतः उसके प्रति कानून बनाना उचित नही ठहरता । इसके लिये समाज को समझाने जाग्रत करने और सशक्त बनाने की आवश्यकता होती है

इस बात को सती प्रथा के उदाहरण से समझा जा सकता है जब अंग्रेज भारत आये तब यहां सती प्रथा का बोलबाला था। अंग्रेजी कानून लागू हो चूके थे पर अंग्रजो ने सती प्रथा रोकने का कानून नही बनाया । उस पर सोचा भी नही । कहा जा सकता है कि इस बारे मे सोचने की उन्हे क्या पडी थी । परन्तु बात ऐसी नही थी । उन्होने सामाजिकता और अपराध को अलग करके देखा और समझा। राजा राममोहन राय ने इस दिशा मे पहल की । राजाराममोहन से शासन का कुछ विमर्श हुआ होगा ,परन्तु सती प्रथा रोकने का कानून बना दिया गया।

विवाह व्यवस्थाएँ आठ प्रकार की हैं । प्रेम विवाह भी इन आठ में से ही एक है ।

हर माता पिता सन्तान को बड़े अरमानों से पालते हैं । यदि सन्तान के मनमाने कृत्य से उनके मनसूबों पर , उनके अरमानों पर पानी फिरता है तो उन्हें हत्याओं जैसी जटिल स्थितियों का सामना करने तक की नौबत आ जाती है । हालांकि फिल्म जगत ने इस समस्या को बहुत कुछ हल कर दिया है । ऐसी स्थिति में यह भी देखने में आया है कि यौवन के नशे में जब किसी के कदम डगमगा जाते हैं और दोनों पक्षों को पछताना पड़ता है तब उनके अभिभावकों की स्थिति अधिक विकट हो जाती है । वैसे यह स्थिति आज अभिभावकों द्वारा देखभाल कर किये गये विवाहों में भी धोखे के कारण उत्पन्न होने लगी है ।

गान्धर्व विवाह में भी दो स्थितियाँ बनती हैं एक तो अन्तरजातीय विवाह की , दूसरी सगोत्र विवाह की । अंतर्जातीय विवाह दो प्रकार के होते हैं : अनुलोम विवाह – उची जाति का पुरुष निम्न जाति की कन्या, प्रतिलोम विवाह– उच्च वर्ण की कन्या निम्न वर्ण का पुरुष । आजकल भारत सरकार उत्थान के नाम पर अनुलोम विवाह को प्रोत्साहित करती है । इस प्रकार के अंतर्जातीय विवाह विवाद और उलझन के कारण बनते हैं । एक ओर अंतरजातीय विवाह है जो किसी विदेशी से किया जाता है ।

मेरी दृष्टि में सबसे गंभीर संबन्ध सगोत्र विवाह का है । इससे यदि अभिभावकों को ज्ञान हो तो उन्हें अपनी संतान को उससे होने वाली नैसर्गिक हानि को समझना चाहिये । सगोत्र विवाह कभी भी अच्छा नहीं होता क्योंकि एक तो उसके प्रच्छन्न परिणाम कभी भी अच्छे देखने में नहीं आते हैं । दूसरे सगोत्र विवाह से उत्पन्न संतान अपेक्षा कृत अपरिपक्व ,किंवा कतिपय कमजोरियाँ लिये होती हैं कानूनी व्यवस्था चाहे जो हो । इस विषय को आनुवंशिकी (मत्पकपजल)विषय से बेहतर समझा जा सकता है । मुझे लगता है कि जहाँ शासन स्कूलों में यौन शिक्षा देने की बात करता है वहाँ ऐसे स्वस्थ विषयों को छुआ जा सकता है । अमेरिका का एक प्रकरण तो ऐसा देखने में आया था जहाँ सगे भाई बहनो में संबंध स्थापित हो गया है और भाई ने बमुश्किल उस स्थिति से पिण्ड छुड़ाया । यो पाश्चात्य समाज में कौटुम्बिक व्यभिचार विशेष बात नहीं ।

यहाँ महाभारत का उदाहरण उल्लेखनीय है । यह कितना मान्य हो पायगा ,नहीं कहा जा सकता । महाभारत में राजा शान्तनु मायावती की संताने चित्रांगद ओर विचित्रवीर्य असमय मृत्यु को प्राप्त हुई । उनके संतान भी नहीं हुई । अब प्रश्न यह था कि हस्तिनापुर का शासक कौन होगा ? वेदव्रत(भीष्म) तो राजा न बनने की प्रतिज्ञा कर चुके थे तब भीष्म ने नियोग की बात की । इसे मायावती ने मान तो लिया किन्तु नियोग के लिये उसने अपने ही पुत्र वेदव्यास को प्रसन्न किया । परिणाम यह हुआ कि दोनों रानियों से नियोग करने पर दोनों बार उपयुक्त सन्तान प्राप्त नहीं हो सकी । महाभारत में उसे जिस ढंग से भी वर्णित किया गया हो परन्तु वह स्थिति माता के गर्भ से जन्मे व्यक्ति से नियोग के कारण सफल नहीं हो सका । पहली बार में संतान अन्धी हुई तो दूसरी बार पीली अथवा रूग्ण । तीसरी बार नियोग रानी से न होकर दासी से हो गया । परन्तु संतान श्रेष्ठ उत्पन्न हुई । किन्तु दासी पुत्र होने से विदुर राजा बनने योग्य नहीं माने गये । तथ्य यह है कि यदि नियोग मायावती के पुत्र से न होकर अन्य किसी योग्य राजपुरुष या वैसे कोटि के किसी अन्य पुरुष से सम्पन्न कराया होता तो बात बन सकती थी । यही कारण है कि चाणक्य ने राजनीति में राजा को विदेशी राजा की कन्या से विवाह को उपयुक्त बताया है ।

इस प्रकार स्थितियों को समझने के लिये इतिहास है ,सिद्धान्त है और व्यवहारिकता भी है । बड़ी कमी यह है की आज का मानव, विशेष रूप से भारतीय , केवल आगे दौड़ना चाहता है । उसे

पुरातन को जानने में न तो रुचि है और न उसमें आस्था । ऐसे में आवश्यकता इस बात की भी है कि विवाह की सही वयःसन्धि होती है उसी का पालन करना चाहिये । परन्तु भारत सरकार ने इस आयु पर भी नियंत्रण कर लिया है । भारत सरकार ने विवाह की आयु को भी कानून में बांध दिया गया है उसे इस परिणाम से कुछ लेना देना नहीं है कि इस व्यवस्था से समाज को किस गर्त में धकेला जा रहा है ।

लेख की अन्य बातें –

कानून ने सगोत्र विवाह को वैध घोषित किया.....

वस्तुतः कानून बनाते समय प्राकृतिक नियम और मान्यताओं को ध्यान में रखा जाता है और रखा जाना चाहिये । परन्तु ऐसा नहीं होगा

पहले संवैधानिक हस्तक्षेप शून्य था ।

यही श्रेष्ठ और आदर्श स्थिति होती है । विवाह मौलिक अधिकार है परन्तु उसका दुरुपयोग होने पर पारिवारिक सामाजिक बहिष्कार ही पर्याप्त है और वही होना चाहिये ।

अंग्रेजी शासन ने व्यक्ति परिवार और समाज की सारी अवधारणाओं को उलट पलट कर रख दिया ।

वह शासन जानता था कि यदि उन्हें अपने पैर यहाँ जमाने हैं तो वही एक रास्ता है इसलिये उसने वही किया । उन्होंने विधि में पति पत्नी को अलग माना । आयकर या आय को लेकर भी व्यक्ति को ही मान्यता दी । कांग्रेस पार्टी कागठन अंग्रेज ह्यूम ने किया था । भारतीयों ने विशेष रूप से नेहरू के सान्निध्य में, कांग्रेस में शामिल होकर न केवल हिन्दुत्व को अपितु राष्ट्रियता को भी घटा बता दी थी । यह कहा जा सकता है । आज वही विचार धारा फूल फल रही हैं ।

अब एक ही विचार धारा हावी है कि परिवार और समाज व्यवस्था समाप्त करके राज्य या व्यक्ति को सर्वाधिकार सम्पन्न बनाया जाय । यही कुटनीति है कि अब इसके परिणाम भी देखने में आने लगे हैं –छोटी-छोटी बातों को लेकर जनता सरकार का मुँह ताकने लगती है , फलस्वरूप सरकार इसे अपनी अहमियत मान कर फूल जाती है ।

हमारे राजनेता झगड़े पैदा तो करना जानते हैं पर सुलझा नहीं पाते हैं । झगड़े पैदा ही इसलिये किये जाते हैं कि वे चलते रहे और वे अपनी रोटियाँ सेकते रहे । अतः यह कहना ठीक नहीं है कि सुलझा नहीं पाते, बल्कि सुलझाना ही नहीं चाहते । पैदा किये गये झगड़े सुलझाने के लिये नहीं होते हैं । इतिहास साक्षी है । चित्रकार ,पत्रकार ,कलाकार, के सदृश्य नेता समस्याकार हैं

संविधान में हमारे कर्तव्यों को उनका अधिकार घोषित करके झगड़ा पैदा कर दिया ।

बन्दर के हाथ में उस्तरा पकड़ना इसी को कहते हैं । बन्दर क्या जाने कि उसका नतीजा क्या होगा ।

(श्री एम एस सिंगला , अजमेर, राजस्थान)

देश के राष्ट्रगान के रूप में अपनाए गये गीत 'जन गन मन अधिनायक.....' के रचयिता कवीन्द्र रवीन्द्र हैं । उन्होंने यह रचना किंग जार्ज 5 के भारत आगमन पर सन 1911 में उनके सम्मान में की थी । अंग्रेजों को यह रचना अति रुचिकर लगी । स्वाभाविक है कि जब ब्रिटिश शासक को भारतीयों के जन गन के मन

को अधिनायक और उसके भाग्य विधाता बता दिया जाय तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है । मान्यता तो यहा तक है कि कवीन्द्र रवीन्द्र को उनकी रचना गीतांजली पर नोबल पुरस्कार प्रदान किया जाना भी इसी रचना का प्रतिफल था ।

वाइसराय लार्ड वेवल के चलते अंग्रेज शासन ने इस देश की एक कमजोरी भाप ली थी । उसे अंजाम देने व उसका लाभ उठाने के लिये उसने केवल लार्ड माउण्टबैटन को यहाँ भेजा । माउण्टबैटन ने नेहरू को ही देश के प्र. मंत्री के योग्य होना करार दिया । ऐसी बड़ी घटनाओ मे बड़ी बड़ी घटनाएँ छिपी होती है । जो अनुमान और परिस्थितियों से ही समझी समझाई जा सकती है ।

देश को आजाद करने मे नेहरू और माउण्टबैटन के बीच कुछ अति गुप्त समझौते हुए जिनके चलते देश केवल राजनैतिक रूप से आजाद हो सका था । भारत के आजाद होने के पीछे अनेक बाते थी । जिन्हे नेहरू से मनवा ली थी । कहा जा सकता है कि ब्रिटिश ने चाहा था कि आजाद हिन्दुस्तान का राष्ट्रगान इसे ही रखा जाय । यहा नेहरू की तनिक मानसिकता की झलक पा लेनी चाहिये । नेहरू मन से पूर्ण निरंकुश शासन मे विश्वास करने वाला व्यक्ति था । उसकी वह महत्वाकाक्षा लोकतंत्र के जरीये ही पूरी हो सकती थी जो हुई । समझा जा सकता कि इस मानसिकता चलते इस गीत मे यदि भारतीय राजनेताओं को वही गौरव बरबस मिल जाय तो क्यो छोडा जाय । तब से समझिये कि यह कांग्रेस की पसंद रहा ।

उक्त संकेत के बाद यदि कोई भी भारतीय इन कुछ प्रश्नो पर विचार करे तो उसे वस्तु स्थिति की झलक मिल सकती है । देश का नाम 'इण्डिया ' ही क्यो रहने दिया गय ? देश का राष्ट्र धर्म क्यो नही घोषित किया गया? देश मे केन्द्रिय राजभाषा का मामला क्यो उलझा कर छोड दिया गया? जब ऐसे तत्वो को ही नजर अंदाज कर दिया गया तब राष्ट्रीय पशु पक्षी या राष्ट्र चिन्ह ही निर्धारित करना मात्र कुछ औपचारिकताएँ पूरी करके आम जन भ्रमित करना था ।

यह सोच सही नही है कि मुसलमानो के भय से वन्दे मातरम को राष्ट्रगान घोषित नही किया गया । नेहरू ने अपने पहले राष्ट्रपति की परवाह न करते हुए हिन्दु कोड बिल ही क्यो और कैसे पास करवाया । जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट की भी विपरीत प्रतिक्रिया है ? सच तो यह है कि देश पर कोई राष्ट्रीय कृत्य लागू नही है । राष्ट्र मात्र 'अखिल भारत का अर्थ देने के काम आता है । ऐसी बातो को लेकर आज राजनेताओ को छोडकर आम जन यह महसूस करने पर मजबूर है कि राष्ट्रवादी तो भारत माता पर प्राण निछावर कर गये, अब तो भारत को नोच कर खाने वाले शेंष बचे है ।

राष्ट्रगान लम्बे समय से विवाद का विषय रहा है तथ पत्र पत्रिकाओ मे प्रयाप्त सामग्री प्रकाशित हो चुकी है ।

विस्तार मे बहुत कुछ कहा जा सकता है किन्तु स्थिति की तह तक पहुचने के लिये इतने तथ्य ही प्रयाप्त होने चाहिये ।

पत्र बहुत समय के बाद लिख पा रहा हूँ । क्षमा करें । स्वास्थ्य ठीक नही रहता है तथा कुछ विपरित परिस्थितियों है ।

उत्तर – आपने जो विचार रखे है उन पर मेरी कुछ सहमति है और कुछ असहमति भी । व्यक्ति परिवार और समाज के अधिकारो की सीमाओ पर विचार करने की जरूरत है । पश्चिम परिवार और समाज को

कोई अधिकार देने के विरुद्ध है। पश्चिम के अनुसार व्यक्ति सम्पूर्ण अधिकार सम्पन्न इकाई है। व्यक्तियों की सहमति से ही समाज बनता है। भारत में समाज स्वयं को सर्व शक्तिमान इकाई मानता है। समाज का ही नवीनतम रूप राज्य बन गया है। राज्य न परिवार को मानता है न समाज को क्योंकि समाज तो वह स्वयं ही है। व्यक्ति को उसने कुछ अधिकार छोड़ ही रखे हैं। बीच में न परिवार है न समाज। इस अस्पष्टता के कारण ही टकराव होते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो पुरातन सस्कृति से इस सीमा तक चिपटे हैं कि वे नया संशोधन सुनने को भी तैयार नहीं। कुछ अन्य लोग ऐसे हैं जो हर नये को ही ठीक मानने को तैयार हैं। इन्हें हर पुरातन में पिछड़े पन की गंध आती है। मेरा विचार है कि नये या पुराने का विवाद छोड़कर यथार्थ की चर्चा करें। सबसे पहले यह तय करें कि व्यक्ति परिवार समाज और राज्य के अधिकारों की सीमाएँ क्या हों?

राष्ट्रगान सम्बन्धी चर्चा में आपने नेहरू और लार्ड माउन्टबैटन के बीच किसी गुप्त संधि का उल्लेख किया। संभव है कि आपको किसी गुप्त संधि की जानकारी हो। किन्तु मुझे नहीं होने से मैं स्वयं को दूर रखना चाहता हूँ। मैं नेहरू जी को सत्ता संघर्ष का एक हिस्सा तो मानता हूँ किन्तु हर मामले में नेहरू जी का विरोध करना मेरा स्वभाव नहीं है। पिछले ज्ञानतत्व में मैंने आपको अपना समझकर कुछ गर्मा गर्म उत्तर दे दिये थे जिससे नाराज होकर आपने प्रश्न करना ही बन्द कर दिया था। अब मैं वैसी स्थिति नहीं आने देना चाहता हूँ। मेरी प्राथमिकता है विचार मंथन और आपकी है प्रचार प्रसार। आप जिसे ठीक मानते हैं उसका प्रचार करते रहते हैं। मेरा मार्ग भिन्न है। मेरे विचार में आप जहाँ ठीक हैं, उसे मैं छोड़कर आगे बढ़ जाता हूँ। जहाँ असहमति है उन्हीं मुद्दों पर मैं तर्क वितर्क करता हूँ। इस मत भिन्नता के कारण कई साथी नाराज हो जाते हैं किन्तु सोचिये कि यदि आपकी मजबूरी है तो मेरी भी तो कुछ मजबूरी है।

(झ)अपनी से अपनी बात

कई माह आपसे अपनी बात पर संदेश का आदान प्रदान नहीं हुआ। अब कुछ योजना बन पाई है। अपनी से अपनी बात में योजना का प्रारूप प्रस्तुत है। आप भी अपने सुझाव भेज सकते हैं।

पचीस दिसम्बर चौरासी तक मैं अंतिम रूप से समझ चुका था कि सत्ता के माध्यम से किन्हीं समस्याओं का रूपान्तरण तो हो सकता है किन्तु समाधान नहीं। पचीस दिसम्बर चौरासी को मैंने राजनीति छोड़कर घोषित किया कि मैं पचीस दिसम्बर दो हजार नौ तक अनुसंधान तथा उनके निष्कर्षों के आधार पर समस्याओं के समाधान का मार्ग खोज लूंगा। मैंने पूरा प्रयत्न किया। अनुसंधान कार्य अभूतपूर्व रूप से सफल रहा। विश्व की अनेक समस्याओं के कारण और समाधान बताने की स्थिति में हम पहुँच सकते हैं। किन्तु हम समाधान का मार्ग खोलने में सफल नहीं हो सके। समाधान सिर्फ एक था। “लोक स्वराज्य” रिसर्च का प्रयोग पूरा हो चुका था। दो हजार पाँच के प्रारम्भ तक स्पष्ट दिखता था कि सफलता निश्चित है। ठाकुर दास बंग पूरी तरह सहमत थे तथा अमरनाथ भाई दुविधा में थे। सर्वोदय के सामान्य कार्यकर्ता दो भागों में बटे हुये थे। सिद्धराज जी लगभग सहमत थे। किन्तु अन्य उच्च पदाधिकारी या तो तटस्थ थे या विरुद्ध। कार्यकारिणी की बैठक में मैं तो जा नहीं सकता था। बंग जी को अलग थलग कर दिया जाता था। समर्थक दब जाते थे। और विरोधी हावी हो जाते थे। सर्वोदय नेतृत्व से निराश होकर मैंने दिल्ली को अपना स्वतंत्र कार्यालय बनाया। गोविन्दाचार्य जी पर आशा की किरण जगी किन्तु शीघ्र ही अनुभव हुआ कि अभी उनका सत्ता मोह समाप्त नहीं हुआ। फिर से घूम फिर कर बंग जी पर ही सारी

